

झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान सभा

सप्तम (शीतकालीन) सत्र
वर्ग-05

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक- 26 अक्टूबर, 1943 (श0) को
17 दिसम्बर, 2021 (ई0)
झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सं०सं०	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
30/10 (01)*	अ0सू0-11	श्री प्रदीप यादव	विजली दर में सुधार करना। ऊर्जा		12.12.21
(02)*	अ0सू0-02	श्री समीर कुमार मोहंती	ढाटा इंड्री की खानियों को दूर करना।	राजस्व नि. एवं भू.सु।	12.12.21
(03)*	अ0सू0-29	सुश्री अम्बा प्रसाद	विकास कार्यों को क्रियान्वयन करना।	राजस्व नि. एवं भू.सु।	12.12.21
(04)*	अ0सू0-33	श्री मनीष जायसवाल	दाखिल खारिज को दुरुस्त करना।	राजस्व नि. एवं भू.सु।	12.12.21
(05)*	अ0सू0-27	श्री निरल पुट्टी	विद्युत मीटर को अधिकृत करना।	ऊर्जा	12.12.21
(06)*	अ0सू0-21	श्री बंधु तिर्की	पूर्ण भू-सर्वेक्षण करवाना	राजस्व नि. एवं भू.सु।	12.12.21
(07)*	अ0सू0-18	डॉ० सरफराज अहमद	विधि आयोग का कार्यकाल विस्तार करना।	विधि	12.12.21
(08)*	अ0सू0-17	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	द्रजपात एवं आपदा से ग्रस्त के परिवार को चार लाख रु० एवं नौकरी देना।	ऊर्जा	12.12.21
(09)*	अ0सू0-19	श्री बंधु तिर्की	दोषियों पर कार्रवाई।	स.वि.शि.एवं परि.कल्याण।	12.12.21
(10)*	अ0सू0-03	डॉ० लम्बोदर महतो	दोषियों पर कार्रवाई।	ऊर्जा	12.12.21

(11)-	A0S00-28	श्री रामदास सोरेन	दोषी पर कार्रवाई एवं कार्यों को पूर्ण करना।	अनु.ज.अनु. जन.एवं पि.व.क।	12.12.21
(12)-	A0S00-25	श्री अमर कुमार बाउरी	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना चालू करना।	अनु.ज.अनु. जन.एवं पि.व.क।	12.12.21
(13)-	A0S00-23	श्री भानू प्रताप शाही	S.I.T जॉब रिपोर्ट पर कार्रवाई।	राजस्व नि. एवं भू.सु.	12.12.21
(14)-	A0S00-15	डॉ० कुशवाहा शशिशूषण मेहता	जीवन रक्षक चिकित्सा उपलब्ध कराना।	स.वि.शि.एवं परि.क.	12.12.21
(15)-	A0S00-12	श्री प्रदीप यादव	बिजली बिल की माफी	ऊर्जा	12.12.21
(16)-	A0S00-09	श्री विनोद कुमार सिंह	मेडिकल बीमा पाँच लाख की जगह दस लाख करना।	विधि	12.12.21
(17)-	A0S00-08	श्री अमित कुमार यादव	प्रवासी मजदूरों की मृत्यु पर पाँच लाख का भुगतान। एवं	भ्रम.नि.प्र. को.वि.	12.12.21
(18)-	A0S00-01	श्री समीर कुमार मोहंती	D.P.S की माफी एवं वन टाईम सेटलमेंट करना।	ऊर्जा	12.12.21
(19)-	A0S00-10	श्री सुदेश कुमार महतो	वेतनभंगारी मासिक भत्ता उपलब्ध कराना।	भ्रम.नि.प्र. एवं को.वि.	12.12.21
(20)-	A0S00-13	श्री विट्ठी नारायण	दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई।	राजस्व नि. एवं भू.सु.	12.12.21
(21)-	A0S00-30	श्री दीपक बिरुवा	विद्युतीकरण बहाल करना।	ऊर्जा	12.12.21
(22)-	A0S00-04	श्री स्टीफन मराण्डी	विद्युत ग्रिड का निर्माण।	ऊर्जा	12.12.21
(23)-	A0S00-05	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	कौशल विकास प्रशिक्षण को प्रखण्ड स्तर पर चालू करना।	विधि	12.12.21
(24)-	A0S00-06	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	मकान एवं भूमि के एवज में बैंक ऋण उपलब्ध कराना। एवं	राजस्व नि. भू.सु.	12.12.21
(25)-	A0S00-34	श्री राजीव सरदार	प्रोत्साहन राशि वंचित डॉक्टरों को करना।	स.वि.शि.एवं परि.क.	12.12.21
(26)-	A0S00-20	डॉ० सरफराज अहमद	स्वतंत्र अधिवक्ता रखने के संबंध में।	विधि	12.12.21
(27)-	A0S00-31	श्री दीपक बिरुवा	प्रोत्साहन राशि प्रदान करना।	स.वि.शि.एवं परि.क.	12.12.21
(28)-	A0S00-16	श्री रामचन्द्र सिंह	भू-सर्वेक्षण तक रशीद करना स्वगित करना।	राजस्व नि. एवं भू.सु.	12.12.21
(29)-	A0S00-07	श्री अमित कुमार मंडल	अवुष्मान कार्डधारियों को निजी अस्पताल में मुक्त रखना उपलब्ध कराना।	स.वि.शि.एवं परि.क.	12.12.21
(30)-	A0S00-24	श्रीमती पुष्पा देवी	योजनाओं को क्रियान्वयन।	अनु.ज.अनु. जन.एवं पि.व.क.	12.12.21
(31)-	A0S00-22	श्री नलिन सोरेन	दुमका के शिकारीपाड़ा में सौ शैया वाले छात्रावास का निर्माण।	अनु.ज.अनु. जन.एवं पि.व.क.	12.12.21

* → विधि विभाग, डे जॉर्नाल - 1805, दिनांक - 14.12.21 डे द्वारा
 नम. नियोजन, प्रशिक्षण एवं डोशनल विभाग डे स्थानांतरित।

- (32)- अ0सू0-14 श्री विट्ठी नारायण धर्मतिरण को रोकना। अनु.ज.अनु. 12.12.21 जन.एवं पि.व.क।
- (33)- अ0सू0-26 श्री सरयू राय बन्दोबस्त कर घर का होलिंग सं0 देना। राजस्व नि. 12.12.21 एवं भू.सु।
- (34)- अ0सू0-32 श्री मनीष जायसवाल अद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को धालू करना। क्रम.नि.प्र. 12.12.21 एवं को.वि।

राँधी

दिनांक:-17 दिसम्बर,2021 (ई0):

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा,राँधी।

झाप संख्या:-झा0वि0स0-(प्रश्न)-06/2020-.....2473...../वि0स0,राँधी,दिनांक:- 15/12/2021

प्रतिलिपि :-झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण, मुख्यमंत्री/अन्य मंत्रिगण, संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकसुवक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनाई प्रेषित।

सैयद जावेद हैदर
15/12/21
(सैयद सहाय)
अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँधी।

झाप संख्या:-झा0वि0स0-(प्रश्न)-06/2020-.....2473...../वि0स0,राँधी,दिनांक:- 15/12/2021

प्रतिलिपि :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक (सचिबीय कार्यालय) को कनरा: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनाई प्रेषित।

सैयद जावेद हैदर
15/12/21
अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँधी।

झाप संख्या:-झा0वि0स0-(प्रश्न)-06/2020-.....2473...../वि0स0,राँधी,दिनांक:- 15/12/2021

प्रतिलिपि :-कार्यवाही शाखा,वेबसाईट शाखा,ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा,झारखण्ड विधान सभा को सूचनाई प्रेषित।

सैयद जावेद हैदर
15/12/21
अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँधी।

3
15.12.21

संलग्न

01

श्री प्रदीप यादव, मांसविंसो द्वारा दिनांक 17.12.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अंसू-11 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्ता श्री प्रदीप यादव, मांसविंसो	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में प्रतिदिन 2200 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि राज्य अपने संसाधनों से मात्र 400 मेगावाट बिजली ही उत्पादन कर पा रहा है;	स्वीकारात्मक। राज्य में स्थापित विद्युत संयंत्र की क्षमता निम्नवत् है:- शिवीद्विरी जल परियोजना - 2x65 MW तेनुपाट ताप विद्युत घर - 2x210 MW
3. क्या यह बात सही है कि PTPS, NTPC को हस्तान्तरण के शर्तों में से एक शर्त यह भी था कि NTPC 500 मेगावाट बिजली पुरानी यूनिट से देगी जो अबतक अप्राप्त है;	NTPC, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड एवं झारखण्ड सरकार के बीच हुए संयुक्त उद्यमी समझौते दिनांक 29.07.2015 के अनुसार पुराने यूनिट से 115-120 मेगावाट बिजली देने का प्रावधान था। लेकिन पर्यावरण एवं अन्य कारणों की वजह से पुराने यूनिट का संचालन नहीं हो पाया एवं उसके एवज में NTPC द्वारा कौरवा एवं फरक्का-III से 50-50 मेगावाट की विद्युत आपूर्ति की जा रही है।
4. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड बिजली बोर्ड को वाह्य स्रोतों से बिजली खरीदने में अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है जिसका खर्च आम जनता को उठाना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा वहन सभी खर्चों के आधार पर निगम द्वारा झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रतिवर्ष ARR/Tariff Petition दायर की जाती है। तदुपरांत निगमक आयोग के द्वारा निगम तथा आम जनता के पक्षों की समुचित सुनवाई के उपरांत ही, विद्युत दर का निर्धारण किया जाता है न कि सिर्फ निगम के प्रारस्तावित वार्षिक टेरिफ के आधार पर।
5. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बिजली के अपने स्रोतों के बारे में विचार रखती है ताकि उपभोक्ताओं को बिजली सुनिश्चित एवं सही दर पर मिल सके, हाँ, तो कब तक, नहीं क्यों ?	पतरातू में प्रथम चरण में 3x800=2400 MW विद्युत संयंत्र Patratu Vidyut Utpadan Nigam Limited (PVUNL) की स्थापना प्रक्रियाधीन है, जिसकी पहली यूनिट 800MW की संचालन 2023-24 में संभावित है, तथा अन्य इकाईयों की स्थापना छः माह के अंतराल में संभावित है, इस प्रकार राज्य के जनता को गुणवत्ता पूर्ण बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2409 /

दिनांक 16-12-2021

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार रोय)
सरकार के अवर सचिव।

सुश्री अम्बा प्रसाद, संवि०स० के द्वारा पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ०सू०-29 का उत्तर प्रतिवेदन :-

क्र	प्रश्न	उत्तर
	सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय संवि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राजस्व विभाग के पत्रांक-510/नि०रा०, दिनांक-24.09.2018 द्वारा उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को निर्देशित करते हुए सभी उपायुक्त/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को सरकारी बंदोबस्त प्राप्त भूमि एवं सरकारी भूमि पर अवस्थित संरचना का मुआवजा भुगतान करने के आलोक में तथा मुख्यमंत्री सचिवालय के पत्रांक-3600972, दिनांक-14.09.2021 के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने हजारीबाग उपायुक्त को जिले में अधिग्रहित की गई गैरमजरूआ भूमि के लंबित भुगतान करने का निदेश दिया है,	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार के शापांक-10/डी०एल०ए० विधि(नीति)-19/08-334/रा०, दिनांक-14.05.2009 के आलोक में राज्य के सभी उपायुक्त को केन्द्र सरकार के लोक उपक्रमों की परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित गैरमजरूआ खास भूमि के 30 वर्षों से अधिक अवधि के दखलदार पाए जाने वाले भू-स्वामियों को सामान्य रैयतों को देय मुआवजा के समतुल्य मुआवजा राशि देने का प्रावधान है,	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त सभी आदेशों का अभी तक अनुपालन न करते हुए बड़कागाँव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत एनटीपीसी, पीटीपीएस आदि प्रतिष्ठानों में अधिग्रहित गैर मजरूआ भूमि पर दखल कब्जा रखने वाले रैयतों को रैयती भूमि के अनुरूप मुआवजा और अन्य लाभ नहीं दिया जा रहा है तथा अधिग्रहित क्षेत्र में एनओसी एवं अन्य कारणों की वजह से विकास कार्यों का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है,	विभागीय संकल्प के अनुसार गैरमजरूआ खास जमीन के मामले में जिला प्रशासन के द्वारा किये गये स्थानीय जाँच के आधार पर मुआवजा भुगतान की कार्यवाही एनटीपीसी के द्वारा (CBA Act के तहत) की जाती है। प्रासंगिक मामले में गैर मजरूआ भूमि का अवैध तरीके से मुआवजा भुगतान के आरोप के संबंध में पूर्व में राज्य सरकार के द्वारा विशेष जाँच दल का गठित किया गया था। जाँच दल के द्वारा मुआवजा भुगतान में अनियमितता बरतने का प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। साथ ही साथ गैरमजरूआ भूमि के मुआवजा भुगतान के मामले में CBI के द्वारा जाँच की जा रही है। उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में गैरमजरूआ खास भूमि के मुआवजा भुगतान के संबंध में अत्यधिक सावधानी बरतते हुए भुगतान की जाती है।

<p>4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बड़कागँव विधान सभा अंतर्गत अधिग्रहित की गई या की जा रही गैरमजबूत भूमि का मुआवजा भुगतान रैयती भूमि के बराबर वर्तमान दर पर करने तथा अधिग्रहित क्षेत्र में विकास कार्यों का क्रियान्वयन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?</p>	<p>उपरोक्त कड़िका-3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।</p>
---	--

**झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।**

ज्ञापांक-02ए0/मू0अ0नि0 (वि0स0) अ0सू0-244/2021 *595/2021* रौंची, दिनांक-16-12-2021

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक-2310, दिनांक-12.12.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड रौंची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड रौंची/विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा-12(समन्वय) को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
सरकार के उप सचिव।

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

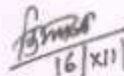
श्री मनीष जायसवाल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-17.12.2021 को पूछा जानेवाला
अल्प-सूचित प्रश्न संख्या- अ0सू0-33 का प्रश्नोत्तर :-

क्र.	प्रश्न	उत्तर																												
	श्री मनीष जायसवाल, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।																												
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग सहित राज्य के लगभग सभी जिलों में दाखिल-खारिज के साथ-साथ रैयतों द्वारा लगान जमा करने का कार्य बाधित है तथा राज्य में अबतक लगभग कुल-62 हजार दाखिल-खारिज मामले विभागीय लापरवाही में लम्बित है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। दिनांक-15.12.2021 तक जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार हजारीबाग जिला में दाखिल-खारिज के 8243 मामले सहित पूरे राज्य में कुल-67923 मामले लम्बित हैं।																												
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड-01 में वर्णित मामले को सेवा की गारंटी अधिनियम अन्तर्गत 90 दिनों के अन्दर निष्पादित करने का प्रावधान है परन्तु उक्त अधिनियम का उल्लंघन पर सरकार संबंधित पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है ;	स्वीकारात्मक। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-11086, दिनांक-29.12.2016 द्वारा झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा-3 के अंतर्गत दाखिल-खारिजवादों के निष्पादन हेतु समय-सीमा अधिसूचित किया गया है। दाखिल-खारिज सेवा के लिए नियत-समय सीमा की विवरणी इस प्रकार है :- <table border="1"> <thead> <tr> <th>Services</th> <th>Designated Officer</th> <th>Time limit</th> <th>1st Appellate Authority</th> <th>Time limit for Disposal of 1st Appeal</th> <th>2nd Appellate Authority</th> <th>Time limit for disposal of 2nd Appeal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>दाखिल-खारिजवादों का निष्पादन-आपत्ति रहित वाद</td> <td>अंचल अधिकारी</td> <td>30 days</td> <td>भूमि सुधार उप समाहर्ता</td> <td>30 days</td> <td>समाहर्ता /अपर समाहर्ता</td> <td>30 days</td> </tr> <tr> <td>दाखिल-खारिजवादों का निष्पादन-वाद जिसमें आपत्ति दाखिल की गयी हो।</td> <td>अंचल अधिकारी</td> <td>90 days</td> <td>भूमि सुधार उप समाहर्ता</td> <td>30 days</td> <td>समाहर्ता /अपर समाहर्ता</td> <td>30 days</td> </tr> <tr> <td>दाखिल-खारिजवादों का निष्पादन-अंतिम आदेश की तिथि के प्रभाव में संशोधन पर्वी का निर्गमन</td> <td>अंचल अधिकारी</td> <td>03 days</td> <td>भूमि सुधार उप समाहर्ता</td> <td>30 days</td> <td>समाहर्ता /अपर समाहर्ता</td> <td>30 days</td> </tr> </tbody> </table>	Services	Designated Officer	Time limit	1 st Appellate Authority	Time limit for Disposal of 1 st Appeal	2 nd Appellate Authority	Time limit for disposal of 2 nd Appeal	दाखिल-खारिजवादों का निष्पादन-आपत्ति रहित वाद	अंचल अधिकारी	30 days	भूमि सुधार उप समाहर्ता	30 days	समाहर्ता /अपर समाहर्ता	30 days	दाखिल-खारिजवादों का निष्पादन-वाद जिसमें आपत्ति दाखिल की गयी हो।	अंचल अधिकारी	90 days	भूमि सुधार उप समाहर्ता	30 days	समाहर्ता /अपर समाहर्ता	30 days	दाखिल-खारिजवादों का निष्पादन-अंतिम आदेश की तिथि के प्रभाव में संशोधन पर्वी का निर्गमन	अंचल अधिकारी	03 days	भूमि सुधार उप समाहर्ता	30 days	समाहर्ता /अपर समाहर्ता	30 days
Services	Designated Officer	Time limit	1 st Appellate Authority	Time limit for Disposal of 1 st Appeal	2 nd Appellate Authority	Time limit for disposal of 2 nd Appeal																								
दाखिल-खारिजवादों का निष्पादन-आपत्ति रहित वाद	अंचल अधिकारी	30 days	भूमि सुधार उप समाहर्ता	30 days	समाहर्ता /अपर समाहर्ता	30 days																								
दाखिल-खारिजवादों का निष्पादन-वाद जिसमें आपत्ति दाखिल की गयी हो।	अंचल अधिकारी	90 days	भूमि सुधार उप समाहर्ता	30 days	समाहर्ता /अपर समाहर्ता	30 days																								
दाखिल-खारिजवादों का निष्पादन-अंतिम आदेश की तिथि के प्रभाव में संशोधन पर्वी का निर्गमन	अंचल अधिकारी	03 days	भूमि सुधार उप समाहर्ता	30 days	समाहर्ता /अपर समाहर्ता	30 days																								
		विभागीय पत्रांक-1039, दिनांक-04.03.2021 द्वारा दाखिल-खारिजवादों के निष्पादन हेतु अधिसूचित समय-सीमा में दाखिल-खारिजवादों का निष्पादित नहीं किये जाने पर झारखण्ड																												

		सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा-7 एवं 08 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अंचल अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय पदाधिकारी पर कार्यवाही करने हेतु सभी उपयुक्त, झारखण्ड को निदेश दिया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड-01 में वर्णित मामले के संबंध में संबंधित पदाधिकारियों द्वारा हमेशा इन्टरनेट सेवा बाधित रहने का बहाना बनाकर राज्य वास्तियों को परेशान किया जा रहा है, जो जांच का विषय है ;	विभागीय पत्रांक-602, दिनांक-06.11.2018 एवं विभागीय पत्रांक-639, दिनांक-29.01.2020 द्वारा ऑनलाईन म्यूटेशन, लगान, निबंधन, इन्टरगैरेशन ऑफ डाटा आदि में उदभुत तकनीकी समस्याओं/त्रुटियों के निराकरण हेतु क्रमशः राज्य सूचना पदाधिकारी एवं सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, झारखण्ड, राँची को निदेश दिया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड-1 में वर्णित मामले का स्थाई समाधान एक माह के अन्दर करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कॉडेका-02 एवं 03 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

**झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।**

झापांक- 6/वि0स0- (अल्प-सूचित)-323/2021/4277/रा0, दिनांक-16-12-2021
प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके झापांक-2312/वि0स0, दिनांक-12.12.2021 के प्रसंग में उत्तर की 10 (दस) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा-12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


16/11/2021
सरकार के अवर सचिव।

05

श्री निरल पुरती, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-27 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्ता श्री निरल पुरती, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला अन्तर्गत तांतनगर प्रखण्ड में विद्युत उपभोक्ताओं को "राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना" एवं "सौभाग्य योजना" के तहत दो विद्युत मीटरों का अधिष्ठापन किया गया है;	इस संबंध में कार्यालय को शिकायत अप्राप्त है।
2. क्या यह बात सही है कि एक ही उपभोक्ता को दोनों विद्युत मीटर द्वारा विद्युत विपन्न निर्गत किया जा रहा है;	-वही-
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपभोक्ताओं को विद्युत विपन्न भुगतान हेतु किसी एक योजना के विद्युत मीटर को अधिकृत करने का विचवार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं क्यों?	इस तरह के मामले प्राप्त होने पर जाँच की जाएगी। जाँचोपरान्त मामला सही पाए जाने पर एक मीटर को हटाकर उपभोक्ताओं को सिर्फ एक ही विद्युत विपन्न निर्गत किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार,

ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2406 /

दिनांक 16-12-2021

प्रतिलिपि- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार राय)
सरकार के अवर सचिव।

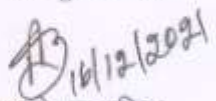
06

श्री बंधु तिर्की, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक-17.12.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या-अ०सू०-21 का उत्तर प्रतिवेदन :-

क्र	प्रश्न	उत्तर
	श्री बंधु तिर्की, माननीय स०वि०स०	प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला के रिविजनल सर्वे का प्रकाशन CNT ACT 1908 की धारा 84(2) के तहत वर्ष-2005 में किया गया, जिसके आधार पर भूमि संबंधी संपूर्ण कार्य किया जा रहा है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि DILMP के तहत हाल सर्वे के अनुसार भू-अमिलेखों का Digitize कराकर जिले के सभी भूमि संबंधी कार्य हो रहा है, परन्तु रिविजनल सर्वे में अनेको त्रुटियाँ विद्यमान रहने के कारण भू-विवादों एवं भू-समस्याएँ व्याप्त है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि आदिवासियों की धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूमि यथा सरना, जाहेस्थान, देशावली, देवस्थान, मसना, हड़गडी, डालीकतारी, भूतखेता, पहनाई, महतोई, पईनमरा, कोटवारी, जतर स्थल, अखड़ा, घुमकुडिया, बकारत, मुण्डा आदि भूमि को पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा रैयती खाता दर्ज कर दिया गया है, जिसके कारण उपरोक्त प्रकार की भूमि की खरीद-बिक्री की जा रही है.	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या-438/नि०रा०, दिनांक-31.10.2019 के द्वारा रिविजनल सर्वे त्रुटिपूर्ण होने के कारण लातेहार जिला के अंतिम प्रकाशित सातों अंचलों के राजस्व ग्रामीणों का छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1902 की धारा-98 के तहत निहित प्रावधान के आलोक में पूर्ण भू-सर्वेक्षण (Re-Survey) का कार्य प्रारंभ करने पर विचार रखती है, हाँ, यदि तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	अधिसूचना सं०-438/नि०रा०, दिनांक-31.10.2019 के आलोक में रि-सर्वे कार्य प्रारंभ करने की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
(भू-अर्जन निदेशालय)

ज्ञापक-02/भू०अ०प०नि०, वि०स० (अ०सू०)-61/2021-694/नि०रा०, राँची, दिनांक-16-12-2021
प्रतिलिपि- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक-2294/वि०स०, दिनांक-12.12.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा-12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।

07

डॉ सरफराज अहमद, माननीय सदस्य, झारखंड विधान-सभा द्वारा दिनांक-17.12.2021 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-18 का संशोधित उत्तर सामग्री।

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि विधि विभागीय अधिसूचना संख्या-2618/जे0 दिनांक-14.11.2002 के द्वारा झारखंड राज्य विधि आयोग का गठन दो वर्षों के लिए किया गया था;	- स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखंड राज्य विधि आयोग का विस्तार दिनांक-14.11.2019 तक किया गया है, परंतु आयोग के अध्यक्ष/सदस्य एवं पदाधिकारियों की नियुक्ति आज तक नहीं हुई है;	- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। झारखंड राज्य विधि आयोग का कार्यकाल की अवधि विधि विभागीय अधिसूचना संख्या-972/जे0 दिनांक-30.07.2021 द्वारा दिनांक-13.11.2021 तक के लिए विस्तारित की गई है, परंतु दिनांक-31.10.2014 तक ही अध्यक्ष का नियुक्ति/पदस्थापन रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखंड राज्य विधि आयोग का कार्यकाल दिनांक-14.11.2019 से आगे विस्तारित कर अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति करने का विचार रखती है; हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	- वस्तुतः दिनांक-14.11.2002 को झारखंड राज्य विधि आयोग गठन के उपरान्त लगातार समय-समय पर इसकी अवधि विस्तारित की गई। समय-समय पर आयोग को दिये गये अवधि विस्तार में आयोग में सविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा का अवधि विस्तार दिया जाता रहा है। उक्त आयोग में दिनांक-31.10.2014 तक अध्यक्ष का नियुक्ति/पदस्थापन रहा है। दिनांक 01.11.2014 से दिनांक 13.11.2021 तक आयोग की अवधि विस्तारित तो की गई है, परन्तु उक्त अवधि में अध्यक्ष/सदस्य सचिव के पद पर किसी की नियुक्ति/पदस्थापन नहीं किया गया है। दिनांक-14.11.2021 से आयोग की अवधि का विस्तार एवं आयोग के अध्यक्ष/सदस्य सचिव एवं पदाधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार
विधि विभाग

ज्ञापक-ए0/विधि-वि0स0प्र0-44/2021-1831/जे0 राँची, दिनांक-16 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपि- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या-2286/वि0स0, दिनांक-12.12.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(मलिन कुमार)
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।

18

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-17 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्ता श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में ऊर्जा विभाग की लापरवाही से किसी व्यक्ति की मृत्यु विद्युत तार विच्छेद या अन्य कारणों से होने पर मृतक के परिजन/ आश्रित को मात्र दो लाख रुपये मुआवजा राशि भुगतान करने का प्रावधान है;	आंशिक स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि राज्य में वज्रपात (प्राकृतिक आपदा) से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर सरकार द्वारा आपदा मुआवजा राशि के रूप में चार लाख रुपये मृतक के परिजन/ आश्रित को भुगतान करने का प्रावधान है;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि विभागीय लापरवाही के कारण विद्युत विभाग द्वारा राज्य में अधिष्ठापित जर्जर विद्युत तारों के चपेट में आने से प्रतिवर्ष कई लोग मृत्यु अथवा आजीवन शारीरिक विकलांगता के शिकार होते हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ऊर्जा विभाग की लापरवाही/ विद्युत तार विच्छेद के चपेट में आने से मृत अथवा शारीरिक विकलांगता के शिकार होने वाले व्यक्ति के परिजन/आश्रित को मिलने वाले मुआवजा राशि में वृद्धि कर वज्रपात (प्राकृतिक आपदा) के शिकार मृतकों को मिलने वाले आपदा मुआवजा राशि के अनुरूप चार लाख रुपये भुगतान करने तथा मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विद्युत स्पर्शाघात की घटना में मृत होने वाले व्यक्ति के परिजन/आश्रित को वर्तमान में मिलने वाले मुआवजा राशि में वृद्धि कर मुआवजा राशि ₹० 4,00,000/- (रुपये चार लाख) मात्र किये जाने हेतु अनुशंसा झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को भेजी गई है। झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड स्तर से निर्णयोपरंत उक्त प्रावधान झारखण्ड विजली वितरण निगम लिमिटेड में स्वतः लागू हो जायेगी। निगम के नियमानुसार मृतक के आश्रित को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2410 /

दिनांक 16-12-2021

प्रतिलिपि- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार राय)
सरकार के अवर सचिव।

**श्री बंधु तिर्की, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.12.2021 को पूछा जानेवाले
अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-19 का उत्तर प्रतिवेदन।**

<p>1. क्या यह बात सही कि राँची जिलान्तर्गत ईटकी यक्ष्मा आरोग्यशाला में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 300 बेड का कोविड सेंटर तीन माह के अन्दर निर्माण करने का निर्देश दिया गया था ;</p>	<p>स्वीकारात्मक।</p>
<p>2. क्या यह बात सही कि माननीय मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश के बाद भी लगभग 8 माह गुजर जाने के बाद भी आरोग्यशाला के इन्टर और महिला वार्ड को विकसित नहीं किया जा सका है ;</p>	<p>अस्वीकारात्मक। उपरोक्त, राँची के ज्ञापांक 1623 (II) दिनांक 26.10.2021 एवं ज्ञापांक 129 (I) दिनांक 30.11.2021 के अनुसार वैश्विक महामारी कोविड-19 के संभावित तीसरी लहर को देखते हुए प्रथम फेज में इन्टर वार्ड में 150 बेड की व्यवस्था की जा रही है साथ ही द्वितीय फेज में एन0डब्लू0डब्लू वार्ड में ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था की गई है। विद्युत आपूर्ति की सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में 200 KVA का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापित करने हेतु कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, राँची को निर्देश दिया जा चुका है। तथा वार्ड में पहुँच पथ के लिए 1250 मीटर पी0सी0सी0 पथ का निर्माण कार्य कराने के लिए तकनीकी स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य स्कीम अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग के अधीन ईटकी आरोग्यशाला, ईटकी, राँची में प्रस्तावित कोविड अस्पताल (300 बेड) के सुचारु संचालन हेतु ईटकी आरोग्यशाला के परिसर में पी0सी0सी0 पथ के निर्माण की योजना के लिए कुल 58,94,700/- (अनठावन लाख चौरानबे हजार सात सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति विनागीय पत्र संख्या-59 (5) ब दिनांक 16.12.2021 द्वारा प्रदान कर दी गयी है।</p>
<p>3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के अवहेलना कर कार्य में शिथिलता भरतने वाले दोषी अधिकारियों को दंडित करने पर विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?</p>	<p>उपरोक्त कॉडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।</p>



10

डॉ लम्बोदर महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-03 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्ता डॉ लम्बोदर महतो, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि दिनांक-19.11.2021 को TTPS Lalpania के GM & DGM के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से बिना स्थानीय विधायक/सांसद की उपस्थिति में पर्चा के नाम पर्चा सत्यापन प्रतिदिन वैसे 40 रैयतों को वितरित किया गया जिसका पर्चा लगभग 35 वर्ष रैयतों को दिया जा चुका है;	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि उक्त सरकारी कार्यक्रम में मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल समन्वय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद स्थानीय माननीय सांसद व विधायक को आमंत्रित किया गया है;	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक- 266, दि०-04.03.2016 के आलोक में जिले में किसी भी योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन समारोह में स्थानीय विधायक/सांसद को आमंत्रित किया जाना निदेशित है। वर्णित कार्यक्रम किसी योजना के शिलान्यास अथवा उद्घाटन से संबंधित नहीं है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उक्त कठिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,

ऊर्जा विभाग

ज्ञापक 2413 /

प्रतिलिपि- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूत्रनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक 16-12-2021



(अजय कुमार राय)
सरकार के अवर सचिव।

श्री रामदास सोरेन, मा०स०वि०स० से प्राप्त दिनांक-17.12.2021 को पूछे जाने वाले वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या-28 का उत्तर प्रतिवेदन:-

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला प्रखण्ड स्थित काडाडुबा पंचायत के काडाडुबा ग्राम में वर्ष-2007-2008 में सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातीय आवासीय विद्यालय के छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण कार्य प्रारंभ की गई थी;	आंशिक स्वीकारात्मक। उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के पत्रांक-2289, दिनांक- 15.12.2021 के अनुसार तारामणी उच्च विद्यालय काडाडुबा घाटशिला में 50 शय्या अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास निर्माण योजना का योजना संख्या 24/08-09 है। छात्रावास का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2008-09 में ही प्रारंभ की गई थी। योजना निर्माण हेतु श्री रामबदन महतो, कनीय अभियंता (प्रभारी) मेसो क्षेत्र जमशेदपुर विभागीय अभिकर्ता नियुक्त थे।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड-01 में वर्णित निर्माण कार्य की राशि की निकासी विभागीय पदाधिकारियों एवं सम्बन्धित संवेदक की मिलीभगत में कर उक्त कार्य को अब तक लम्बित छोड़ दिया गया है जिसका लाभ स्थानीय छात्रों को नहीं मिल पा रहा है	योजना की प्राक्कलित राशि 56,15,147.00 रु० है। योजना का मापी पुस्त में कुल राशि 56,00,407.00 रु० का मापी दर्ज है। अभिकर्ता को कुल राशि 55,00,407.00 रु० का भुगतान किया जा चुका है। उक्त छात्रावास बनने के पश्चात् लगभग दो से डेढ़ वर्ष तक पुलिस पिकेट के रूप में उपयोग किया जा रहा था। वर्तमान में छात्रावास खाली है। उपायुक्त द्वारा सूचित किया गया है कि छात्रावास की मरम्मत की आवश्यकता है। विभाग द्वारा उपायुक्त से मरम्मत हेतु प्रस्ताव की माँग की गई है। प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त विभाग द्वारा मरम्मत हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि आवंटित कर दी जाएगी। मरम्मत के उपरान्त छात्रावास को अखिलम्ब तारामणी उच्च विद्यालय, काडाडुबा, घाटशिला को हैंडओवर कर दी जाएगी।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार जनहित में खण्ड-01 में वर्णित कार्यों में लापरवाही करने वाले पदाधिकारियों पर आवश्यक कार्रवाई कर उक्त कार्य को चालू वित्तीय वर्ष में पूरा कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कठिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापक-10 / Article 275(1)-वि०स०नि० 15 / 2021 - 3244

राँची, दिनांक-16/12/2021

प्रतिलिपि-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप संख्या-2309, दिनांक-12.12.2021 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रशाखा-6 (विधायी कार्य), अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सुनी कुमारी)

सरकार के अवर सचिव।

12

श्री अमर कुमार बाउरी सं० वि० सं० से प्राप्त दिनांक- 17.12.2021 को पूछे जाने वाला
अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-अ०सू०-25 का उत्तर-

क्र०	अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-अ०सू०-25	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार ने सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना दूरे देश में लागू की है?	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना झारखण्ड सरकार ने अपने राज्य में लागू नहीं किया है जिस कारण राज्य के लाखों अनुसूचित जाति समाज के युवा इस छात्रवृत्ति का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं?	अस्वीकारात्मक। राज्य में पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना लागू है। इस योजना अंतर्गत छात्र-छात्राओं द्वारा e-kalyan पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 23863 एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में 26681 अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना हेतु नया मार्गनिर्देश लागू किया गया है। नए मार्गनिर्देश के अंतर्गत पूर्व के प्रावधान Committed Liability के स्थान पर केन्द्र और राज्य के बीच 60:40 की sharing पद्धति लागू की गई है। इससे राज्य सरकार को लाभ मिला है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति के 51993 छात्र-छात्राओं द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु e-kalyan पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया गया है। विभाग द्वारा राज्य का share 40% राशि जिलों को आवंटित किया जा चुका है। शेष 60% राशि का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा की जानी है।
	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या राज्य सरकार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना राज्य में लागू करने की मंशा रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त खण्डों में वस्तुनिधित स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापक-03/वि०सं०(अल्प-सूचित)- 3243

रांची, दिनांक- 16/12/21

प्रतिलिपि- 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापक सं०-2282 दिनांक- 12.12.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याभ प्रेषित।

(सुमिता कुमारी)
सरकार के अवर सचिव।

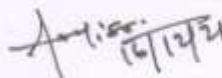
13

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय संवि०स० द्वारा दिनांक-17.12.2021 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या-23 की उत्तर सामग्री।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री भानु प्रताप शाही, माननीय संवि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के हेहल अंचल स्थित खाता सं०-119, प्लॉट सं०-336, थाना नं०-140, मौजा-बजरा स्थित भूमि से संबंधित अभिलेखों की जाँच हेतु सरकार द्वारा नियुक्त श्री अंजनी कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया था।	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि गठित SIT के द्वारा अपने जाँच रिपोर्ट विभाग को समर्पित कर दिया गया है।	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार SIT जाँच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	जाँच प्रतिवेदन के आलोक में कार्रवाई सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक :-9/आरोप-राँची (वि०स०अ०सू०)-281/2021-4278/रा०, दिनांक-16-12-2021
प्रतिलिपि :- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक-2291/वि०स०, दिनांक-12.12.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय प्रशाखा-12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री कशवाहा शशिशुभषण मेहता, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा
दिनांक-17.12.21 को पूछा जाने वाला अल्प सुचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-15 का उत्तर
प्रतिवेदन।

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि पलामू जिले में कोरोना महामारी काल में संक्रमित मरीजों की संख्या के अनुरूप अस्पतालों में बेड की उपलब्धता कम होने तथा चिकित्सा व्यवस्था अपर्याप्त होने के कारण अधिकांश मरीजों को राँची तथा अन्य शहरों में जाना पड़ा था, जहाँ की दूरी अधिक होने के कारण कई गंभीर मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते थे;	अस्वीकारात्मक। मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पलामू में कोरोना महामारी काल में मरीजों की सुविधा हेतु पर्याप्त बेड उपलब्ध था तथा 31 गंभीर मरीजों को रिम्स, राँची में रेफर किया गया। किसी भी गंभीर मरीज के रास्ते में दम तोड़ने की सूचना प्राप्त नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि आज पूरा विश्व कोरोना महामारी की तीसरी लहर (ओमिक्रॉन वरिएंट) को लेकर आशंकित तथा भयभीत है तथा वैश्विक स्तर पर इससे बचाव की तैयारी की जा रही है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि मेदिनीनगर, पलामू के पोखराहा में पलामू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का भव्य आधारभूत संरचना बन कर तैयार है, परन्तु आजतक इत्तको चिकित्सीय सुविधा युक्त बनाकर प्रारम्भ नहीं किया जा सका है ;	अस्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पलामू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को आधुनिक चिकित्सा सुविधा से सुसज्जित कर शीघ्रतारोघ प्रारंभ कराकर पलामू जिले के मरीजों को जिले के अन्दर ही पर्याप्त मात्रा में उच्चस्तरीय जीवन रक्षक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हों, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज के पास मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पलामू का भवन निर्माणाधीन है। वर्तमान में सदर अस्पताल, पलामू को उत्कृष्टित कर चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 9/विद्ययी-06-22/2021 - 572(9)

राँची, दिनांक-15/12/21

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०-2297 दिनांक-12-12-2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


15.12.21
सरकार के अवर सचिव

15

श्री प्रदीप यादव, मांसवि०स० द्वारा दिनांक 17.12.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-12 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्ता श्री प्रदीप यादव, मांसवि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार ने ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल का बकाया भुगतान में Delay Payment Surcharge को माफ करने की योजना लागू की है;	स्वीकारात्मक। ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को "एकमुश्त समझौता योजना" के तहत विलंब शुल्क अविभार की राशि में छूट प्रदान की जा रही है। उक्त योजना दिनांक 31.12.2021 तक लागू है।
2. क्या यह बात सही है कि इस योजना का लाभ उठाने में उपभोक्ताओं को बिजली बिल में व्यापक गड़बड़ी एवं अड़चन पैदा हो रही है;	अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपभोक्ताओं के कठिनाईयों की ध्यान में रखते हुए बिजली बिल में हुई गड़बड़ी में त्वरित संशोधन हेतु एक विशेष अभियान चलाना चाहती है ताकि उपभोक्ताओं को बिजली बिल माफी योजना का लाभ मिल सके, हाँ, तो कब तक, नहीं क्यों ?	"एकमुश्त समझौता योजना" का लाभ उठाने वाले ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के विपन्न में यदि झुट्टि संज्ञान में आता है, तब संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा विपन्न संशोधित किया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बड़े पैमाने पर "एकमुश्त समझौता योजना" के प्रचार प्रसार हेतु कैंप का आयोजन किया जा रहा है। उक्त कैंप में उपभोक्ताओं के विद्युत विपन्न में संशोधन का कार्य भी किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार,

ऊर्जा विभाग

ज्ञापक 2411 /

प्रतिलिपि- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक 16-12-2021

(अजय कुमार राय)
सरकार के अवर सचिव।

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय सदस्य, विधान सभा, झारखण्ड, राँची द्वारा दिनांक-17.12.2021 को सदन में पूछे जाने वाले अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-09 का उत्तर सामग्री।

	अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-09	उत्तर सामग्री
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण अधिनियम 2018, विधानसभा से पारित होने के बावजूद आज तीन साल पश्चात् भी इसके आलोक में नियमावली नहीं बनाई गई है ;	:- अस्वीकारात्मक। विधि विभागीय अधिसूचना संख्या-1270/जे0, दिनांक-10.09.2021 के द्वारा Jharkhand Advocate's Clerks Welfare Fund Rules, 2020 गठित की जा चुकी है।
2.	क्या यह बात सही है कि कोविड संकट में पाबंदियों के कारण वकीलों के भी आर्थिक संकट बढ़े हैं ?	:- आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपरोक्त तथ्य सत्य है तो क्या सरकार तत्काल नियमावली बनाते हुए उसमें 5 लाख रुपये की मेडिकल बीमा और 10 लाख का टर्म इशोरेंस की सुविधा देने का प्रावधान रखना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	:- विधि विभाग, झारखण्ड के अधिसूचना संख्या- 457/जे0, दिनांक-24.04.2020 के द्वारा झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि अधिनियम, 2018 की धारा-(4) की उप धारा-(1) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि समिति का गठन किया जा चुका है। झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि अधिनियम, 2018 की धारा-(18) में सदस्यों के लिए समूह जीवन बीमा और अन्य लाभ शीर्षक के अंतर्गत अंकित विंदु निम्नवत हैं :- (क) निधि के सदस्यों के कल्याण के लिए समिति भारतीय जीवन बीमा या किसी अन्य बीमा कम्पनियों से निधि के सदस्यों के जीवन पर समूह बीमा की पॉलिसी लेगी और (ख) निधि के सदस्यों और उनके आश्रितों के लिए यथा विहित चिकित्सीय एवं शैक्षणिक सुविधा तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराएगी। अतएव, अंतर्निहित विषय विंदु झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि समिति के क्षेत्राधीन हैं।

झारखण्ड सरकार,
विधि विभाग,

झापांक-ए0/विधि-(वि0स0प्र0)-45/2021- 1813 /जे0, सीधी, दिनांक- 15 दिसम्बर, 2021
प्रतिलिपि-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सीधी को झाप सं0-2287/वि0स0, दिनांक-12.12.2021 के
प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

Nishu
(नितिन कुमार)
प्रधान सचिव -सह-विधि परामर्शी।

<p>श्री. अरवि कुमार, जिला प्रशासक, जिला प्रशासन, राँची, झारखण्ड।</p> <p>श्री. अरवि कुमार, जिला प्रशासक, जिला प्रशासन, राँची, झारखण्ड।</p> <p>श्री. अरवि कुमार, जिला प्रशासक, जिला प्रशासन, राँची, झारखण्ड।</p>	<p>श्री. अरवि कुमार, जिला प्रशासक, जिला प्रशासन, राँची, झारखण्ड।</p> <p>श्री. अरवि कुमार, जिला प्रशासक, जिला प्रशासन, राँची, झारखण्ड।</p> <p>श्री. अरवि कुमार, जिला प्रशासक, जिला प्रशासन, राँची, झारखण्ड।</p>
<p>श्री. अरवि कुमार, जिला प्रशासक, जिला प्रशासन, राँची, झारखण्ड।</p> <p>श्री. अरवि कुमार, जिला प्रशासक, जिला प्रशासन, राँची, झारखण्ड।</p> <p>श्री. अरवि कुमार, जिला प्रशासक, जिला प्रशासन, राँची, झारखण्ड।</p>	<p>श्री. अरवि कुमार, जिला प्रशासक, जिला प्रशासन, राँची, झारखण्ड।</p> <p>श्री. अरवि कुमार, जिला प्रशासक, जिला प्रशासन, राँची, झारखण्ड।</p> <p>श्री. अरवि कुमार, जिला प्रशासक, जिला प्रशासन, राँची, झारखण्ड।</p>

श्री अमित कुमार यादव, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक-17.12.2021 को पूछे जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न संख्या - 08 का उत्तर सामग्री।

क्र०	प्रश्नकर्ता श्री अमित कुमार यादव, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के पंजीकृत प्रवासी मजदूरों को दुर्घटना से मृत्यु होने पर 1.5 लाख रुपये तथा अपंजीकृत प्रवासी मजदूरों को 1 लाख रुपये मुआवजा राशि का भुगतान प्राधान्य है। जबकि अन्य राज्यों में दुर्घटना से मृत्यु होने पर प्रवासी मजदूरों को 4 लाख रुपया मुआवजा राशि दिया जाता है;	अन्य राज्यों में प्रवास की स्थिति में प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना में मृत्यु होने पर झारखण्ड राज्य के पंजीकृत प्रवासी कर्मचारों को रुपये 1,50,000/- (रुपये एक लाख पचास हजार) एवं अपंजीकृत कर्मचारों को रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख) का भुगतान उनके अश्रितों को किया जाना प्राधान्य है।
2	क्या यह बात सही है कि बिमारी एवं अन्य कारणों से मृत्यु होने पर प्रवासी मजदूरों को किसी प्रकार का मुआवजा राशि नहीं दिया जाता है;	कठिना - 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में किसी भी प्रकार से मृत्यु होने पर प्रवासी मजदूर के परिजन को 5 लाख रुपया मुआवजा देने का प्रावधान करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	कठिना - 1 में वर्णित प्रावधान में परिवर्तन सम्प्रति प्रस्तावित नहीं है।

SM
16/12/2021

(गणेश कुमार)

सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

झापांक-02/श्र0नि0प्र0(वि0स0)-05-17/2021श्र0नि0-1505 राँची, दिनांक-16/12/2021

प्रतिलिपि-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का झाप सं०-2288, दिनांक-
12.12.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

SM
16/12/2021

सरकार के अवर सचिव।

18

श्री समीर कुमार मोहनती, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-01 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्ता श्री समीर कुमार मोहनती, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्र के बकायेदार बिजली उपभोक्ताओं को वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत राहत दी जा रही है;	स्वीकारात्मक। ग्रामीण परेलु उपभोक्ताओं को "एकमुश्त समझौता योजना" के तहत विलंब शुल्क अधिभार की राशि में छूट प्रदान की जा रही है। उक्त योजना दिनांक 31.12.2021 तक लागू है।
2. क्या यह बात सही है कि शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए खण्ड-1 में वर्णित सुविधा उपलब्ध नहीं है;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि शहरी क्षेत्रों में भी खास कर नगर पंचायत क्षेत्र में काफी अधिक संख्या में निर्धन परिवार प्रवास करते हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शहरी क्षेत्रों में भी खास कर नगर पंचायत क्षेत्र में भी डी०पी०एस० माफी करते हुए वन टाइम सेटलमेंट की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापक 2417 /

प्रतिलिपि- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक 16-12-2021

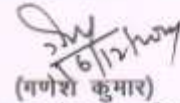
(अजय कुमार राय)
सरकार के अवर सचिव।

19

1510
16/12/2021

श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक-17.12.2021 को पूछे जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न संख्या - 10 का उत्तर सामग्री।

क्र०	प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
	श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय सदस्य, विधान सभा।	श्री सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
	क्या यह बात सही है कि राज्य के नियोजनालयों में लाखों शिक्षित बेरोजगारों के नाम दर्ज हैं;	स्वीकारात्मक है।
	क्या यह बात सही है कि शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिलने या उनके पास जीविकोपार्जन की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है;	राज्य के नियोजनालयों में निबंधित शिक्षित बेरोजगारों को निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोविड-19 हेतु निर्गत मार्गदर्शिका का अनुपालन करते हुए समय-समय पर भर्ती कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है। घालू वित्तीय वर्ष में 89 भर्ती कैम्पों का आयोजन कर 1,915 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं।
	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिलने या जीविकोपार्जन की उचित व्यवस्था नहीं होने तक मासिक भत्ता देने की इच्छा रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को मासिक भत्ता देने हेतु सरकार स्तर पर विचाररथीन है।


(गणेश कुमार)

सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापक-02/श्र0नि0प्र0(वि0स0)-05-16/2021श्र0नि-1510 राँची, दिनांक-16/12/2021
प्रतिलिपि-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०-2289, दिनांक-
12.12.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याभ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।

(20)

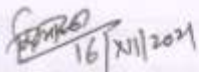
श्री बिरंघी नारायण, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-17.12.2021 को पूछा जानेवाला
अल्प-सूचित प्रश्न संख्या- अ०सू०-13 का प्रश्नोत्तर :-

क्र.	प्रश्न	उत्तर																												
	श्री बिरंघी नारायण, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।																												
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो सहित राज्य के सभी जिलों में करीब 20,000 से अधिक दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) के मामले लंबित हैं, जबकि राज्य में झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम प्रभावी है, और इसके अंतर्गत आपत्ति वाले म्यूटेशन के मामलों को 90 दिनों में एवं बिना आपत्ति वाले म्यूटेशन के मामलों को 30 दिनों के अंदर निष्पादित करने का स्पष्ट प्रावधान है ;	<p style="text-align: center;">आशिक स्वीकारात्मक</p> <p>दिनांक-15.12.2021 तक जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार बोकारो जिला में दाखिल-खारिज के 3991 मामले सहित पूरे राज्य में कुल-67923 मामले लंबित हैं।</p> <p>कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजनाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-11086, दिनांक-29.12.2015 द्वारा झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा-3 के अंतर्गत दाखिल-खारिज यादों के निष्पादन हेतु समय-सीमा अधिसूचित किया गया है।</p> <p>दाखिल-खारिज सेवा के लिए नियत-समय सीमा की विवरणी इस प्रकार है :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Services</th> <th>Designated Officer</th> <th>Time limit</th> <th>for Appellate Authority</th> <th>Time limit for Disposal of 1st Appeal</th> <th>2nd Appellate Authority</th> <th>Time limit for disposal of 2nd Appeal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>दाखिल-खारिज यादों का निष्पादन - आपत्ति सहित याद</td> <td>अवल अधिकारी</td> <td>30 days</td> <td>भूमि सुधार उप समारहता</td> <td>30 days</td> <td>समारहता /अपर समारहता</td> <td>30 days</td> </tr> <tr> <td>दाखिल-खारिज यादों का निष्पादन-याद जिसमें आपत्ति दाखिल की गयी हो।</td> <td>अवल अधिकारी</td> <td>90 days</td> <td>भूमि सुधार उप समारहता</td> <td>30 days</td> <td>समारहता /अपर समारहता</td> <td>30 days</td> </tr> <tr> <td>दाखिल-खारिज यादों का निष्पादन - अंतिम आदेश की तिथि के प्रभाव से संबंधित पत्ती का निर्माण</td> <td>अवल अधिकारी</td> <td>03 days</td> <td>भूमि सुधार उप समारहता</td> <td>30 days</td> <td>समारहता /अपर समारहता</td> <td>30 days</td> </tr> </tbody> </table>	Services	Designated Officer	Time limit	for Appellate Authority	Time limit for Disposal of 1 st Appeal	2 nd Appellate Authority	Time limit for disposal of 2 nd Appeal	दाखिल-खारिज यादों का निष्पादन - आपत्ति सहित याद	अवल अधिकारी	30 days	भूमि सुधार उप समारहता	30 days	समारहता /अपर समारहता	30 days	दाखिल-खारिज यादों का निष्पादन-याद जिसमें आपत्ति दाखिल की गयी हो।	अवल अधिकारी	90 days	भूमि सुधार उप समारहता	30 days	समारहता /अपर समारहता	30 days	दाखिल-खारिज यादों का निष्पादन - अंतिम आदेश की तिथि के प्रभाव से संबंधित पत्ती का निर्माण	अवल अधिकारी	03 days	भूमि सुधार उप समारहता	30 days	समारहता /अपर समारहता	30 days
Services	Designated Officer	Time limit	for Appellate Authority	Time limit for Disposal of 1 st Appeal	2 nd Appellate Authority	Time limit for disposal of 2 nd Appeal																								
दाखिल-खारिज यादों का निष्पादन - आपत्ति सहित याद	अवल अधिकारी	30 days	भूमि सुधार उप समारहता	30 days	समारहता /अपर समारहता	30 days																								
दाखिल-खारिज यादों का निष्पादन-याद जिसमें आपत्ति दाखिल की गयी हो।	अवल अधिकारी	90 days	भूमि सुधार उप समारहता	30 days	समारहता /अपर समारहता	30 days																								
दाखिल-खारिज यादों का निष्पादन - अंतिम आदेश की तिथि के प्रभाव से संबंधित पत्ती का निर्माण	अवल अधिकारी	03 days	भूमि सुधार उप समारहता	30 days	समारहता /अपर समारहता	30 days																								
2	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में केवल राजधानी राँची के 22 अंचलों में 9,262 म्यूटेशन के मामले लंबित हैं, इनमें 482 मामले ऐसे हैं, जिसमें कोई भी आपत्ति नहीं है ;	<p style="text-align: center;">आशिक स्वीकारात्मक।</p> <p>दिनांक-18.12.2021 तक दाखिल-खारिज से संबंधित प्रतिवेदन-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">जिला</th> <th colspan="5">कुल लंबित आवेदनों की संख्या</th> <th rowspan="2">कुल अस्वीकृत मामले</th> </tr> <tr> <th>कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या</th> <th>कुल निष्पादित आवेदनों की संख्या</th> <th>कुल लंबित मामले</th> <th>30 दिनों से अधिक और बिना आपत्ति के लंबित मामले</th> <th>90 दिनों से अधिक और आपत्ति के साथ लंबित मामले</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>राँची</td> <td>26983</td> <td>113971</td> <td>14482</td> <td>35</td> <td>300</td> <td>141490</td> </tr> </tbody> </table>	जिला	कुल लंबित आवेदनों की संख्या					कुल अस्वीकृत मामले	कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या	कुल निष्पादित आवेदनों की संख्या	कुल लंबित मामले	30 दिनों से अधिक और बिना आपत्ति के लंबित मामले	90 दिनों से अधिक और आपत्ति के साथ लंबित मामले	राँची	26983	113971	14482	35	300	141490									
जिला	कुल लंबित आवेदनों की संख्या					कुल अस्वीकृत मामले																								
	कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या	कुल निष्पादित आवेदनों की संख्या	कुल लंबित मामले	30 दिनों से अधिक और बिना आपत्ति के लंबित मामले	90 दिनों से अधिक और आपत्ति के साथ लंबित मामले																									
राँची	26983	113971	14482	35	300	141490																								

<p>3 क्या यह बात सही है कि पिछले वर्ष दिसम्बर, 2020 में राँची में ससमय म्यूटेशन निष्पादित न करने पर 16 अंचल अधिकारियों पर झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम के तहत 11.42 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था, जिसका पूर्ण भुगतान अब तक नहीं किया गया है एवं स्थिति और अधिक भयावह होती जा रही है तथा दिन-प्रतिदिन भूमि विवाद के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं ;</p>	<p>आंशिक स्वीकारात्मक राँची समारहणालय, राँची का पत्रांक-553, दिनांक-16.12.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उपायुक्त, राँची के न्यायालय में झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम के तहत कुल-14 (चौदह) अंचल अधिकारियों पर एक माह से अधिक कुल-89 (नवासी) मामले एवं तीन माह से अधिक कुल-111 (एक सौ न्यारह) मामलों पर सुनवाई की जा रही है। जुर्माना में कुल सन्निहत राशि उपायुक्त, राँची के न्यायालय के आदेश के उपरान्त निर्धारित किया जाना है। वर्तमान में उपायुक्त, राँची के न्यायालय में वाद की सुनवाई की जा रही है।</p>
<p>4 यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त लंबित दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) के मामलों को 1 माह में निष्पादित करवाते हुए दोषी पदाधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?</p>	<p>विभागीय पत्रांक-1039, दिनांक-04.03.2021 द्वारा दाखिल-खारिज वादों के निष्पादन हेतु अधिसूचित समय-सीमा में दाखिल-खारिज वादों का निष्पादित नहीं किये जाने पर झारखण्ड सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा-7 एवं 08 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अंचल अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय पदाधिकारी पर कार्यवाही करने हेतु सभी उपायुक्त, झारखण्ड को निदेश दिया गया है।</p>

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक- 8/वि0स0- (अल्प-सूचित)-320/2021/4289/रा0, दिनांक-16-12-2021
प्रतिलिपि- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक-2292/वि0स0, दिनांक-12.12.2021 के प्रसंग में उत्तर की 10 (दस) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा-12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


16/12/2021
सरकार के अवर सचिव।

(21)

श्री दीपक बिरुवा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-30 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्ता श्री दीपक बिरुवा, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला अन्तर्गत टोन्टो प्रखण्ड के टोला उलीवेड़ा में आजादी के 74 वर्षों के बाद भी विद्युतीकरण नहीं किया जा सकता है;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र में विद्युतीकरण हेतु चार वर्ष पूर्व विभाग द्वारा खम्भे गिराये गए जा उस के तस है, जिस कारण इस युग में भी ग्रामीण डिबरीयुग में जीने को मजबूर हैं;	स्वीकारात्मक है।
3. क्या यह बात सही है कि संबंधित क्षेत्र में विद्युतीकरण हेतु विभाग को कई बार ग्रामीणों द्वारा आवेदन दिया जा चुका है;	स्वीकारात्मक है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित क्षेत्र में विद्युतीकरण बहाल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं क्यों?	टोन्टो प्रखण्ड के सागरकट्टा ग्राम के उलीवेड़ा टोला को जनवरी 2022 तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा।

**झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग**

ज्ञापांक 2407 /

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक 16-12-2021

(अजय कुमार राय)
सरकार के अवर सचिव।

22

प्रो स्टीफन मराण्डी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-04 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्ता प्रो स्टीफन मराण्डी, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
<p>1. क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिले के प्रखण्ड कुण्डहित एवं फतेहपुर के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के लोग बिजली की अनियमित आपूर्ति की समस्या से जूझ रहे हैं, इससे निजात अबतक उपभोक्ताओं को नहीं मिल पाया है;</p>	<p>आंशिक स्वीकारात्मक। कुण्डहित एवं फतेहपुर के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में 33/11 के०भी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्र, कुण्डहित से विद्युत आपूर्ति की जाती है। उक्त विद्युत शक्ति उपकेन्द्र में 132/33 के०भी० ग्रिड सब स्टेशन जामताड़ा से विद्युत संप्रेषित की जाती है। 132/33 के०भी० ग्रिड सब स्टेशन जामताड़ा एवं 33/11 के०भी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्र, कुण्डहित की दूरी लगभग 50 कि०मी० है। 33 के०भी० लाईन में खराबी की स्थिति में लम्बी दूरी के कारण फोल्ट को खोजकर ठीक करने में समय लग जाता है जिसके कारण संबंधित क्षेत्र के उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करने में विलंब होती है। वर्तमान में झारखण्ड संपूर्ण आच्छादन योजना (JSBAY) के तहत फतेहपुर प्रखण्ड अन्तर्गत मंझलाडीह में एक 33/11 के०भी० का विद्युत शक्ति उपकेन्द्र निर्माणाधीन है, जिसके पूर्ण होने पर उक्त विद्युत शक्ति उपकेन्द्र से भी फतेहपुर प्रखण्ड के उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी।</p>
<p>2. क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में खर्चित समस्याओं को देखते हुए प्रखण्ड कुण्डहित क्षेत्र में 132KV/ 33KV ग्रिड का अधिष्ठापन हेतु भूमि विन्दित कर कार्य शुरू करने का निर्णय विभागीय स्तर से लिया गया था, परन्तु अबतक कार्य शुरू नहीं हो पाई है;</p>	<p>आंशिक स्वीकारात्मक</p>
<p>3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस क्षेत्र के विद्युत समस्याओं के निदान हेतु विद्युत ग्रिड का निर्माण शीघ्र चालू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं क्यों?</p>	<p>कुण्डहित क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति जामताड़ा स्थित ग्रिड सब-स्टेशन से की जा रही है एवं जामताड़ा ग्रिड को एक मात्र सोर्स मैथन हाइड्रल सब-स्टेशन था, जिसके कारण विद्युत आपूर्ति अनियमित रहती थी। वर्तमान में जामताड़ा ग्रिड को जसीडीह ग्रिड से भी जोड़ दिया गया है। जिसके उपरांत इस क्षेत्र में विद्युत उपलब्धता बढ़ गई है। साथ ही नये ग्रिड बनाने हेतु विशेषज्ञ के द्वारा Load Flow Study कराया गया। जिसमें पाया गया कि वर्तमान परिपेक्ष में कुण्डहित ग्रिड सब-स्टेशन की आवश्यकता नहीं है।</p>

**झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग**

ज्ञापांक 2412 /

दिनांक 16-12-2021

प्रतिलिपि- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार राय)

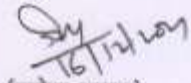
सरकार के अवर सचिव।

23

1507
16/12/2021

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक-17.12.2021 को पूछे जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न संख्या - अ०सू०-05 का उत्तर सामग्री।

क्र.सं.	प्रश्नकर्ता श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण हेतु सरकार द्वारा जिला मुख्यालयों में व्यवस्था की जाती है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य के युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सरकार कृत संकल्पित है। झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी के सूचीबद्ध प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं के द्वारा विभिन्न कौशल योजनाओं के अंतर्गत जिलों एवं प्रखण्डों में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर कौशल प्रशिक्षण कार्य संचालित किये जा रहे हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि कौशल विकास एवं प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी सुदूरपर्वी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे युवक/युवतियों को प्राप्त नहीं होती है, जिससे सरकारी लाभ से लोग वंचित रह जा रहे हैं;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी द्वारा कार्यान्वित कौशल विकास प्रशिक्षण योजनाओं की समस्त जानकारी मिशन सोसाईटी के अधिकृत वेबसाईट http://jsdm-jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है, जिसे कभी भी खोलकर कौशल प्रशिक्षण से संबंधित सभी जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रखण्ड स्तरीय आयोजित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त उत्तर खण्ड - 1 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।



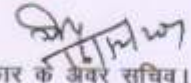
(गणेश कुमार)

सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापक-02/अ०नि०प्र०(वि०स०)-05-19/2021अ०नि०-1507 राँची, दिनांक-16/12/2021
प्रतिलिपि-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०-2284, दिनांक-
12.12.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।

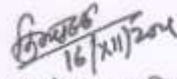
श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-17.12.2021 को पूछा जानेवाला अल्प-सूचित प्रश्न संख्या- अ०सु०-06 का प्रश्नोत्तर :-

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में सी०एन०टी० लागू है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि कुरमी/कुड़नी जाति जो Annexure-1 (अनुलग्नक-1) में आते हैं, और उन्हें बैंक के द्वारा कर्ज का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे उसका विकास प्रभावित हो रहा है एवं आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं ;	<p>आंशिक स्वीकारात्मक।</p> <p>"बिहार शिड्यूल्ड एरियाज रेंगुलेसन" लिस्ट ऑफ बैंकवार्ड क्लासेज के संदर्भ में निर्गत अधिसूचना संख्या- ए/टि०-3043/81-5423-आर, दिनांक-23 जून, 1962 में सी०एन०टी० एक्ट की धारा-46(1)(b) के अन्तर्गत अर्थादित जातियों की सूची के क्रमांक-38 में कुरमी (महती) अंकित है।</p> <p>सी०एन०टी० एक्ट के अन्तर्गत अर्थादित जातियों के गृह निर्माण/व्यवसायिक अग्रिम के मामलों में निबंधन कार्यालय द्वारा जमीन का बंधक पट्टा (Mortgage) मात्र 5 वर्षों के लिए सम्पादित करने के कारण बैंको द्वारा 05 वर्षों के लिए ही गृह निर्माण/व्यवसायिक ऋण दिया जाता है। विदित हो कि छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम (CNT) की धारा-46(1) (a) में निम्नवत् उल्लेख होने के कारण मात्र 05 वर्षों के लिए बंधक पट्टा (Mortgage) किया जाता है :-</p> <p>(a) by mortgage or lease for any period expressed or implied which exceeds or might in any possible event exceed five years, or</p> <p>(बंधक या पट्टे द्वारा अभिव्यक्त ऐसी किसी भी कालावधि के लिए पाँच वर्षों से अधिक हो या किसी भी संभव दशा में अधिक हो सकती हो, अथवा)</p>
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कुरमी/कुड़नी जाति को भूमि एवं मकान के एवज में बैंकों के द्वारा ऋण उपलब्धता सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	<p>CNT की धारा-46(1) (a) का परन्तुक में निम्नवत् उल्लेख है :-</p> <p>Provided that a raiyat may enter into a 'bhugut bundha' mortgage of his holding or any portion thereof for any period not exceeding seven years or if the mortgagee be a society registered or deemed to be registered under the Bihar and Orissa Co-operative Societies Act, 1935 (B&O Act VI of 1935) for any period not exceeding fifteen Years.</p> <p>(परन्तु कोई रैयत अपनी जोत या उनके किसी भाग को, सात वर्षों से अनधिक किसी भी कालावधि के लिए अथवा यदि</p>

		<p>बंधकदार बिहार और उड़ीसा सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 (1935 का बिहार एवं उड़ीसा अधिनियम संख्या-06) के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझी गयी कोई समिति हो तो, 15 वर्षों से अनधिक किसी कालावधि के लिए भुगतबंध बंधक कर सकेगा)</p> <p>छोटानागपुर कारशकारी अधिनियम (CNT) की धारा-46(1) (a) के स्थान पर धारा-46(1)(a) का परन्तुक को आधार मानते हुए गृह निर्माण/व्यवसायिक कार्य हेतु अधिनियम मामलों में जिला निबंधन कार्यालय द्वारा जमीन का बंधक पट्टा (Mortgage) 05 वर्षों के स्थान पर 15 वर्षों के लिए सम्पादित करने पर सी0एन0टी से अधिधित समुदाय के व्यक्तियों को बैंकों द्वारा गृह निर्माण/व्यवसायिक ऋण असाानी से उपलब्ध कराया जा सकता है। इस संदर्भ में विधि (न्दाय) विभाग, झारखण्ड, राँची से भंतव्य प्राप्त कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।</p>
--	--	--

**झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।**

ज्ञापांक- 6/वि0स0- (अल्प-सूचित)-322/2021/रा0, दिनांक-16-12-2021/
 प्रतिलिपि- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक-2290/वि0स0,
 दिनांक-12.12.2021 के प्रसंग में उत्तर की 10 (दस) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल
 सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं
 विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा-12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं
 आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 16/12/2021
 सरकार के अवर सचिव।

25

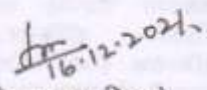
झारखण्ड विधानसभा में श्री संजीव सरदार, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-17.12.2021 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या-34 का उत्तर प्रतिवेदन प्रारूप।

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के चिकित्सा संस्थान में कार्यरत/अध्यनरत पी0जी0 प्रथम वर्ग, कोविड मेडिकल ऑफिसर/हाउस सर्जन चिकित्सक हेल्थ वर्कर्स के द्वारा कोविड महामारी के समय उल्लेखनीय कार्य किये हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा चिकित्सीय क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य संपादित करने वाले कर्मियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने का आदेश निर्गत हुआ था;	आंशिक स्वीकारात्मक। स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं०-54 (7) दिनांक-01.05.2021 के द्वारा कोविड कार्यों में लगे राज्य सरकार के चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों (संविदा सहित) तथा एन0एच0एम0 के अधीन कार्यरत चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल तथा कर्तव्य निर्वहन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें एक माह (अप्रैल-2020) के मूल वेतन/मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि दिये जाने का निर्णय लिया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि सिर्फ चिकित्सक एवं हेल्थ वर्कर्स को ही प्रोत्साहन राशि का भुगतान हुआ जबकि हाउस सर्जन/कोविड मेडिकल ऑफिसर एवं पी0जी0 प्रथम वर्ष को प्रोत्साहन राशि से वंचित किया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। उक्त संकल्प में प्रोत्साहन राशि हेतु राज्य सरकार के चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं स्वास्थ्य विभागीय अन्य कर्मियों (संविदा सहित) तथा एन0एच0एम0 के अधीन कार्यरत चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों जिनके द्वारा COVID-19 Related Contact Tracing, Testing, Supervision कोविड अस्पताल/ कोविड वार्ड में कार्यरत, कार्यालय तथा कंट्रोल रूम में कोविड से संबंधित कार्यों एवं कोरोना वायरस के शोकथाम चिकित्सा में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन किया गया हो, पात्रता रखी गई है। वैसे चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी एवं स्वास्थ्य विभागीय अन्य कर्मी जिनके द्वारा कोविड-19 संक्रमण काल में कोविड-19 से संबंधित कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया है, यह प्रोत्साहन राशि अनुमान्य नहीं है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रोत्साहन राशि से वंचित डॉक्टर इत्यादि को भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कडिका-3 में वर्णित मापदण्ड के आलोक में प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु कर्मी की पात्रता सुनिश्चित करने की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित कार्यालय प्रधान को दी गई है। तदनुसार संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा उपर्युक्त मापदण्ड की परिसीमा में आने वाले चिकित्सक/स्वास्थ्य कर्मी को ही प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है।

क

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 08/विधान सभा(अल्पसूचित)-04/2021 47(08) रौंची, दिनांक-16.12.2021
 प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, रौंची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०-2307 वि० सं० दिनांक-12.12.2021 के प्रसंग में 220 प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।


 (मनोज कुमार सिन्हा)
 सरकार के संयुक्त सचिव

<p>(1) 12-12-2021 को अवर सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के ज्ञाप सं० 08/विधान सभा(अल्पसूचित)-04/2021 47(08) रौंची, दिनांक-16.12.2021 के प्रसंग में 220 प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।</p>	<p>अवर सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के ज्ञाप सं० 08/विधान सभा(अल्पसूचित)-04/2021 47(08) रौंची, दिनांक-16.12.2021 के प्रसंग में 220 प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।</p>
<p>अवर सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के ज्ञाप सं० 08/विधान सभा(अल्पसूचित)-04/2021 47(08) रौंची, दिनांक-16.12.2021 के प्रसंग में 220 प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।</p>	<p>अवर सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के ज्ञाप सं० 08/विधान सभा(अल्पसूचित)-04/2021 47(08) रौंची, दिनांक-16.12.2021 के प्रसंग में 220 प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।</p>
<p>अवर सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के ज्ञाप सं० 08/विधान सभा(अल्पसूचित)-04/2021 47(08) रौंची, दिनांक-16.12.2021 के प्रसंग में 220 प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।</p>	<p>अवर सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के ज्ञाप सं० 08/विधान सभा(अल्पसूचित)-04/2021 47(08) रौंची, दिनांक-16.12.2021 के प्रसंग में 220 प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।</p>

36

डॉ. सरफराज अहमद, माननीय सदस्य, झारखंड विधान-सभा द्वारा दिनांक-17.12.2021 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या-30सू0-20 का उत्तर सामग्री।

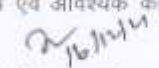
क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत JSRRDA/झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद/उर्जा विभाग के अंतर्गत TVNL/उद्योग विभाग के अंतर्गत लियाडा/झारखंड राज्या खाद्य एवं अतिरिक्त आपूर्ति निगम लिमिटेड/झारखंड राज्य आवास बोर्ड में डा० अशोक कुमार सिंह एवं श्रीमती ऋचा सचिता विद्वान महाधिवक्ता एवं प्रधान सचिव, विधि विभाग के परामर्श से स्वतंत्र अधिवक्ता बनाए गये है.	<p>— आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।</p> <p>विधि विभाग, झारखंड, राँची के अधिसूचना संख्या-439/जे० दिनांक-16.02.2018 द्वारा अधिसूचित The Jharkhand Law Officer (Engagement) Rules, 2018 की कडिका-(3)(7) में निहित प्रावधान निम्नरूपेण है:-</p> <p>"In relation to the Boards, Corporations and other authorities funded and run by the funds of the State Government the engagement of the Retained Counsels or Arguing Counsels shall be made by the concerned Boards, Corporations or other authorities either from amongst the Law Officers engaged for the State Govt. in the Jharkhand High Court or Supreme Court of India on payment of remuneration as prescribed by them or as per the independent decision of such Boards, Corporations and authorities but for that purpose a transparent procedure shall be adopted by them in consultation with the Advocate General of the State of Jharkhand and Principal Secretary, Department of Law (Justice), State of Jharkhand."</p>
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के अन्य 21 संस्थान/निगम/बोर्ड में या विभाग के लिए कोई अन्य अधिवक्ता सेवारत नहीं है।	— अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित संस्थान निगम/बोर्ड/कार्यालय या विभाग के वादों में सरकार का पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र अधिवक्ता रखने का विचार रखती है, हों तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	— कडिका-1 एवं 2 से वस्तुस्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार
विधि विभाग

ज्ञापक-ए०/विधि-वि०स०प्र०-46/2021-1822/जे०

राँची, दिनांक-16 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपि- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या-2285/वि०स०, दिनांक-12.12.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।


 (नलिन कुमार)
 प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
 विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री दीपक बिरुवा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.12.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या-स0-31 का उत्तर प्रतिवेदन।

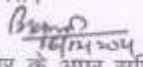
<p>1. क्या यह बात सही है कि राज्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित कार्य शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 महामारी के दौरान घर-घर भ्रमण कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता तथा स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाने में सहियाओं द्वारा अहम भूमिका निभायी जा रही है;</p>	<p>स्वीकारात्मक।</p>
<p>2. क्या यह बात सही कि वर्ष 2007 से वर्ष 2021 तक उक्त सहियाओं को मात्र 2000/-₹ की दर से प्रतिमाह मानदेय राशि दिया जा रहा है ;</p>	<p>अस्वीकारात्मक। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सहियाओं को सामुदायिक गतिविधियों के लिए 2000/-₹ प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि के साथ-साथ 21 विभिन्न स्वास्थ्य गतिविधियों के उत्प्रेरण एवं सहयोग हेतु कार्याधारित प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है, जो MOHFW एवं झारखण्ड सरकार के 60:40 अनुपातिक राशि है। (अनुलग्नक-1) कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता एवं स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाने हेतु सहियाओं को कार्याधारित प्रोत्साहन राशि के साथ ही 1000/-₹ प्रतिमाह की दर से Emergency COVID Response Plan (ECRP) Phase-1 के मद से वर्ष 2021-22 में अप्रैल से मार्च 2022 तक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है।</p>
<p>3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विकट परिस्थितियों में भी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करने वाले सहियाओं को 10,000/-₹ प्रतिमाह मानदेय/प्रोत्साहन राशि देने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</p>	<p>कठिका (2) में वर्णित सहिया के कार्याधारित प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त उन्हें सम्मान पूर्ण प्रति माह 5000/-₹ बतौर मानदेय के लिए माननीय मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचा पत्र माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व रसायन एवं उर्वरक मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली को दिनांक 05.12.2021 को प्रेषित की गई है। (अनुलग्नक -2)</p>

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 21/वि0स0-06-28/2021.12.7(31)

राँची, दिनांक- 16/12/2021

प्रतिलिपि : अपर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापक-2313 वि0स0, दिनांक 12.12.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।

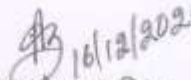
28

श्री रामचन्द्र सिंह, माननीय सावित्री के द्वारा दिनांक-17.12.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या-असू-16 का उत्तर प्रतिवेदन :-

क्र	प्रश्न	उत्तर
	श्री रामचन्द्र सिंह, माननीय सावित्री	प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि विभागीय अधिसूचना 424, दिनांक-05.08.2005 द्वारा प्रकाशित गजट के आलोक में हाल सर्वे के आधार पर लातेहार जिला में सर्वे कार्य किया गया है, उक्त सर्वे में हुई त्रुटियों के कारण भू-स्वामियों को हो रही कठिनाईयों के मद्देनजर अंतिम प्रकाशित सभी अंचलों के राजस्व ग्रामों का पुनः सर्वेक्षण कराने हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या-438, दिनांक- 31.10.2019 निर्गत किया गया है जिसका अनुपालन आज तक नहीं हुआ है;	आंशिक स्वीकारात्मक। विभागीय अधिसूचना संख्या-438, दिनांक-31.10.2019 के आलोक में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित बिना पुनः भू-सर्वेक्षण के खतियान एवं पंजी-2 का मिलाने किये वगैर ऑन लाईन राजस्व लगान काटा जा रहा है जिससे स्थानीय ग्रामीणों को कठिनाई एवं विवाद का सामना करना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। अंतिम प्रकाशित खतियान (पूर्व सर्वे) के आधार पर राजस्व लगान निर्गत किया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जल्द से जल्द पुनः भू-सर्वेक्षण कराने एवं भू-सर्वेक्षण करवाने तक ऑन लाईन रसीद काटना स्थगित रखना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कठिका-1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। सर्वे एक समय लगने वाली प्रक्रिया है। पुनः सर्वेक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक लगान रसीद निर्गत करने की प्रक्रिया को स्थगित रखना जनता के हित में उचित प्रतीत नहीं होता है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
(भू-अर्जन निदेशालय)

ज्ञापांक-02/भूअपनि0, वि0स0 (असू)-62/2021, 695/नि0रा0, राँची, दिनांक-16.12.2021
प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक-2293/वि0स0, दिनांक-22.12.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा-12(समन्वय) को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।

29

झारखण्ड विधानसभा में श्री अमित कुमार मण्डल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-17.12.2021 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या-07 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में नेशनल ब्लड पॉलिसी (SOP) सरकारी एवं निजी अस्पताल पर लागू है;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि कल्याणकारी राज्य में ब्लड (खून) भोंग के आधार पर मुफ्त देने का प्रावधान है;	आंशिक स्वीकारात्मक। सरकारी रक्त केन्द्रों से सरकारी अस्पताल के मरीजों को निःशुल्क रक्त इकाई उपलब्ध करायी जाती है। 2. निजी रक्त केन्द्रों, चेरिटेबल रक्त केन्द्रों एवं कुछ सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र के अधीन संचालित रक्त केन्द्रों द्वारा रक्त इकाई का प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाता है।
3.	क्या यह बात सही है कि विभागीय संकल्प द्वारा अब सरकार ब्लड (खून) भोंग के आधार पर एक निर्धारित राशि की वसूली करेगी;	अस्वीकारात्मक।
4.	क्या यह बात सही है कि राज्य के कोई जिलों में ब्लड बैंक नहीं है या ब्लड बैंक है तो खून के कमी रहने कारण आयुष्मान कार्डधारीयों को मजबूरन निजी अस्पतालों में रक्त के लिए भटकना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जैसे गरीब आयुष्मान कार्डधारीयों के लिए निजी अस्पतालों में बिना किसी प्रोसेसिंग चार्ज के रक्त उपलब्ध कराने की मंशा रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	आयुष्मान कार्डधारीयों के रक्त इकाई से संबंधित प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान आयुष्मान योजना के अन्तर्गत भुगतान होता है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 04/वि० स०-09-02/2021 51 (4)

राँची, दिनांक-15/12/21

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०-2298 वि० स० दिनांक-12.12.2021 के प्रसंग में 220 प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।

(मनोज कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव

30

श्रीमती पुष्पा देवी, सं० वि० सं० से प्राप्त दिनांक- 17.12.2021 को पूछे जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-अ0सू०-24 का उत्तर-

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष झारखण्ड के आदिम जनजाति, अनु० जनजाति, अनु० जाति बाहुल ग्रामों में PVTG एवं गैर PVTG योजना अन्तर्गत PCC सड़क, तालाब, सरना देव स्थल घेराबंदी एवं बुमबुकीया भवन निर्माण करने की योजना है?	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष कब्रिस्तान चाहरदीवारी की योजना भी होती है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में उपर्युक्त वर्णित योजना खासकर पलामू जिले में एक भी योजना बरातल पर न हो पाया है।	अस्वीकारात्मक। जिला कल्याण पदाधिकारी, पलामू के पत्रांक-1020, दिनांक-15.12.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि- 1. वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 06 (छ) सरना स्थल की घेराबंदी योजनाएँ एवं कुल 19 (उनौस) बुमबुकीया भवन निर्माण योजनाएँ स्वीकृत हैं तथा सभी पर कार्य प्रारंभ है। 2. कब्रिस्तान घेराबंदी की विभाग द्वारा स्वीकृत सभी योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत 9 कब्रिस्तान घेराबंदी की योजनाएँ प्रगति पर हैं तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत 10 कब्रिस्तान घेराबंदी की योजनाओं के लिए सामूहिक समिति का चयन किया जा रहा है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित योजनाओं को आदिम जनजाति, अनु० जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों के लाभ हेतु क्रियान्वयन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कठिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

झापाक-06/दि०सं०अल्प०सू०प्र०-04/21- 3250

तारीख दिनांक- 16/12/2021

प्रतिलिपि- 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके झापाक सं०-2081, दिनांक- 12.12.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सुनी कुमारी)
सरकार के अवर सचिव।

31

श्री नलिन सोरेन, मा०स०वि०स० से प्राप्त दिनांक-17.12.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या-22 का उत्तर प्रतिवेदन:-

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला का प्रखण्ड शिकारीपाड़ा अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र है तथा वहीं के लोगों का मुख्य पेशा खेती/किसान एवं मजदूरी है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड शिकारीपाड़ा अन्तर्गत राज्य संपोषित-2 उच्च विद्यालय शिकारीपाड़ा का छात्रावास भवन जर्जर व खंडहर हो गया है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त भवन के जर्जर व खंडहर होने के कारण छात्रों को पढ़ाई करने में दूर दराज से आने वालों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त विद्यालय भवन के जर्जर व खंडहर छात्रावास को ध्वस्त कर छात्रों के हित में 100 (एक सौ) शैक्षिक छात्रावास भवन का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है, हाँ तो जब तक, नहीं तो क्यों?	संविधान के अनुच्छेद 275(1) योजना के तहत अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 के योजना प्रस्ताव में इस योजना को सम्मिलित करते हुए राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करते हुए स्वीकृति हेतु समुचित कार्यवाही की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

आपांक-10 / Article 275(1)-वि०स०नि० 14/2021 - 3245

रौंके, दिनांक-16/12/2021

प्रतिलिपि-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के आप संख्या-2280, दिनांक-12.12.2021 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रशाखा-8 (विधायी कार्य), अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(स्मृती सुमारी)

सरकार के अवर सचिव।

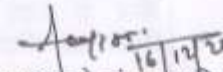
श्री सरयू राय, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक-17.12.2021 को पूछा जानेवाला अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-26 का उत्तर प्रतिवेदन :-

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री सरयू राय, माननीय स0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार ने एक नीतिगत निर्णय के तहत टाटा लीज नवीकरण समझौता-2005 में जमशेदपुर की वैसी 1750 एकड़ जमीन लीज से बाहर कर दिया गया था जिनपर 86 बस्तियाँ बसी थी ;	आंशिक स्वीकारात्मक। टाटा लीज नवीकरण समझौता-2005 में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र के कुल-13 वार्डों की अतिक्रमित भूमि से संबंधित कुल-723.14.55 हे0 = 1786.89 एकड़ भूमि लीज से अलग कर सरकार के खाते में निहित की गयी।
2	क्या यह बात सही है कि बस्तियों की बासगीत भूमि को बाशिंदों के नाम बंदोबस्त करने के लिए ऐसा किया गया था और इस हेतु वर्ष-2006-07 में एक सर्वे भी किया गया था ;	अस्वीकारात्मक। विभागीय अधिसूचना सं-150/सर्वे, दिनांक-15.06.2006 द्वारा जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के वार्ड सं0-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एवं 19 कुल-सोलह वार्डों के सर्वेक्षण एवं खतियान तैयार करने की अधिसूचना निर्गत की गई थी। उक्त अधिसूचना के आलोक में उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक-208/एस0, दिनांक-18.08.2009 द्वारा सर्वेक्षण प्रतिवेदन विभाग को भेजी गई।
3	क्या यह बात सही है कि बस्तियों की आवासित भूमि की बाशिंदों के नाम बंदोबस्ती कर घरों का होल्डिंग नम्बर देने से सरकार को अरबों रुपये की आमदनी होगी मगर बंदोबस्ती की विहित प्रक्रिया शिथिल है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। सरकारी भूमि पर अवैध दखलकारों के साथ अधिकतम 10 डिसिमिल तक आवासीय उद्देश्य हेतु भूमि की लीज बंदोबस्ती करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या-817/रा0, दिनांक-22.02.2018 निर्गत की गयी है, जो उपरोक्त तथाकथित बस्तियों के लिए भी प्रभावी है। उक्त के आलोक में बस्तियों में प्रचार-प्रसार कर कई दिनों तक कैंप लगाया गया था, परन्तु बस्तियावासियों द्वारा रुचि नहीं लेने के कारण लीज बंदोबस्ती की प्रक्रिया नहीं हो पायी।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन बस्तियों की आवासित भूमि को बाशिंदों के नाम बंदोबस्त कर संबंधित संबंधित घरों को होल्डिंग संख्या देने का विचार रखती है, हाँ, तो, कबतक, नहीं तो क्यों?	सरकारी भूमि पर अवैध दखलकारों के साथ अधिकतम 10 डिसिमिल तक आवासीय उद्देश्य हेतु भूमि की लीज बंदोबस्ती करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या-817/रा0, दिनांक-22.02.2018 निर्गत की गयी है, जो उपरोक्त तथाकथित बस्तियों के लिए भी प्रभावी है। वर्तमान में उक्त लीज बंदोबस्ती की शक्ति विभागीय पत्रांक-4064/रा0, दिनांक-25.10.2019 के द्वारा संबंधित उपायुक्त को प्रत्यायोजित की गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

झापांक- 4/वि0स0(अ0सू0)-100/2021. 4285 (4)/रा0 रौंची, दिनांक-16-12-2021

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय को उनके झाप सं0-2296/वि0स0, दिनांक-12.12.2021 के प्रसंग में उत्तर की 5 (पाँच) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रौंची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रौंची/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रौंची एवं विभागीय प्रशाखा-12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।

34

1509
16/12/2021

श्री मनीष जायसवाल, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक-17.12.2021 को पूछा जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-32 का उत्तर सामग्री।

क्र०	प्रश्नकर्ता श्री मनीष जायसवाल माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग विधान सभा क्षेत्र के सदर प्रखण्ड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) स्थापित है परन्तु अबतक-उक्त संस्थान चालू नहीं की गई है;	उत्तर- अस्वीकारात्मक है। हजारीबाग विधान सभा क्षेत्र के सदर प्रखण्ड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हजारीबाग (सिंदूर) चालू अवस्था में है।
2.	क्या यह बात सही है कि सरकार खण्ड-01 में वर्णित संस्थान में पठन-पाठन का कार्य न कराकर उक्त संस्थान में कोविड संस्थान केन्द्र संचालित कर रही है जिसके कारण उक्त क्षेत्र के छात्रों को उक्त संस्थान का लाभ नहीं मिल रही है;	उत्तर- अस्वीकारात्मक है। सदर प्रखण्ड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हजारीबाग (सिंदूर) में कोई कोविड केन्द्र संचालित नहीं है तथा छात्रों को इस संस्थान का लाभ मिल रहा है। वर्तमान में सत्र 2020 एवं 2021 में कुल 595 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छात्रहित में खण्ड-01 में वर्णित संस्थान को चालू शैक्षणिक वर्ष में चालू करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर- कंडिका-1 एवं 2 में उल्लेख है।

SM
16/12/2021
(गणेश कुमार)

सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापक-02/श्र0नि0प्र0(वि0स0)-05-20/2021श्र0नि0-1509 राँची, दिनांक-16/12/2021
प्रतिलिपि-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०-2311, दिनांक-
12.12.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

SM
16/12/2021
सरकार के अवर सचिव।